एलेक्ट्रॉन लाइटिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

बनाम

शाह इनवेस्टमेंट फ़िनन्शियल डेव्लप्मेंट्स एण्ड कंसलटेंट्स

प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील संख्या 9151-9152/2015)

20 नवंबर, 2015

[दीपक मिश्रा और प्रफुल्ल सी. पंत, जे. जे.]

अनुबंध-निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बी. ओ. टी.) के आधार पर स्ट्रीट लाइट बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के साथ मौजूदा स्ट्रीट लाइटों को एल. ई. डी. फिटिंग से बदलने के लिए नगर निगम द्वारा ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गईं-इसके बाद अपीलकर्ता (बोली लगाने वालों में से एक) ने अपनी मूल्य बोली को कम करने की पेशकश की यदि उसे विशेष विज्ञापन अधिकार दिए गए-अपीलकर्ता की तकनीकी बोली स्वीकार कर ली गई जबकि दूसरे बोलीदाता की बोली खारिज कर दी गई-अपीलकर्ता की मूल्य बोली पर बातचीत की गई-अपीलकर्ता को जारी कार्य आदेश-असफल बोलीदाता ने रिट याचिका दायर करके कार्य आदेश के अनुदान को चुनौती दी-उच्च न्यायालय ने कार्य आदेश को रद्द कर दिया-अपील पर कहाः संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का उपयोग जनहित को ध्यान में रखते हुए अनुबंध देने के मामलों में सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए-मामले के तथ्यों में, उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए गलती की कि कार्य आदेश अपीलार्थियों को अवैध रूप से दिया गया था-हालांकि, नगर निगम अपीलार्थियों को इसके लिए निविदा आमंत्रित किए बिना विज्ञापन अधिकार देने में उचित नहीं था-विज्ञापन अधिकारों का अनुदान उस काम का हिस्सा नहीं था जिसके लिए निविदा जारी की गई थी और इसे लागू करते हुए अलग किया जा सकता

था। धारा 57 अनुबंध अधिनियम में निहित पृथकता का सिद्धांत इसलिए, कार्य अनुबंध में दिए गए विज्ञापन अधिकार रद्द कर दिए जाएंगे, जबकि शेष कार्य अनुबंध को बरकरार रखा जाएगा- भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 226- न्यायिक समीक्षा- अनुबंध अधिनियम, 1872 का दायरा- धारा 57- पृथक्करण का डॉसिरिन।

न्यायिक समीक्षा-प्रशासनिक निर्णयों के दायरे और अनुबंध देने में शक्तियों के प्रयोग पर चर्चा की गई।

सिद्धांत/सिद्धांत-पृथकता का सिद्धांत-इसकी प्रयोज्यता।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा और अनुबंध प्रदान करने की शक्तियों के प्रयोग का दायरा इस प्रकार हैः (1) आधुनिक प्रवृत्ति प्रशासनिक कार्रवाई में न्यायिक संयम की ओर इशारा करती है। (2) न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है, बल्कि केवल निर्णय लेने के तरीके की समीक्षा करता है। (3) न्यायालय के पास प्रशासनिक निर्णय को सही करने की विशेषज्ञता नहीं है। यदि प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा की अनुमति दी जाती है, तो यह आवश्यक विशेषज्ञता के बिना अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करेगा, जो स्वयं गलत हो सकता है। (4) निविदा के निमंत्रण की शर्तें न्यायिक जांच के लिए खुली नहीं हो सकती हैं। (5) सरकार को अनुबंध की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हालाँकि, निर्णय का परीक्षण न केवल वेड्सबरी के तर्कसंगतता के सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा किया जाना चाहिए, बल्कि पक्षपात से प्रभावित या दुर्भावना से प्रेरित मनमानेपन से मुक्त होना चाहिए। (6) निर्णयों को रद्द करने से प्रशासन पर भारी प्रशासनिक बोझ पड़ सकता है और इससे बढ़े हुए और बिना बजट के खर्च हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन शक्ति का उपयोग जनहित को ध्यान में रखते हुए अनुबंध देने के मामलों में सावधानीपूर्वक किया

जाना चाहिए। [पैरा 12,13] [107-जी; 108-ए-एच]

टाटा सेल्युलर बनाम भारतीय संघ (1994) 6 एस. सी. सी. 651: 1994 (2) पूरक एस. सी. आर. 122; एयर इंडिया लिमिटेड बनाम कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड और अन्य (2000) 2 एससीसी 617: 2000 (1) एस. सी. आर. 505; जगदीश मंडल अन्य उड़ीसा राज्य और अन्य (2007) 14 एससीसी 517: 2006 (10) पूरक एस. सी. आर. 606- पर निर्भर था।

संजय कुमार शुक्ला बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2014) 3 एस. सी. सी. 493: 2014 (1) एस. सी. आर. 959- संदर्भित।

2.1 उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कानूनी रूप से गलती की है कि कार्य आदेश एल. ई. डी. फिटिंग द्वारा स्ट्रीट लाइटों के प्रतिस्थापन और बी. ओ. टी.- आधार पर स्ट्रीट लाइट बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के संबंध में अपीलार्थियों को अवैध रूप से दिया गया था। [पैरा 19] [113-ए-बी]

2.2 उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ इस आधार पर प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया कि अपीलकर्ता और एलईडी निर्माता के बीच समझौता ज्ञापन को रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था। उच्च न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि किसी भी रिट याचिकाकर्ता ने उस आधार पर अपीलार्थियों की बोली की स्वीकृति को चुनौती नहीं दी थी, और अपीलार्थियों के पास इसे अदालत के रिकॉर्ड पर रखने का कोई अवसर नहीं था। समझौता ज्ञापन निविदा बोली का हिस्सा था, और इसका उल्लेख "निविदा समिति मूल्यांकन रिपोर्ट" में मिलता है। [पैरा 16] {111-सी-डी]

2.3 उच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित अपीलार्थियों के खिलाफ प्रतिकूल दृष्टिकोण रखने का एक अन्य कारण यह है कि अपीलार्थियों द्वारा वैट विवरणी की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गईं। प्रासंगिक वित्तीय वर्षों के लिए वैट रिटर्न का विवरण

तकनीकी बोली के साथ अपीलार्थियों द्वारा विधिवत दाखिल किया गया था। तकनीकी बोलियों के साथ वैट रिटर्न दाखिल करने की पुष्टि "निविदा समिति मूल्यांकन रिपोर्ट" से भी होती है। [पैरा 16] [111-डी-एफ]

2.4 ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम की ओर से अनुबंध देने में कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि निविदा 01.08.2014 पर जारी की गई थी और इसे केवल 03.09.2014 पर अंतिम रूप दिया गया था, यानी एक महीने से अधिक की अवधि के बाद बोली-पूर्व बैठकें आयोजित की गईं और निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दो बार 20.08.2014 से 25.08.2014 और उसके बाद 28.08.2014 तक बढ़ा दी गई, जिससे पता चलता है कि प्रक्रिया जल्दबाजी में नहीं की गई थी। 12.08.2014 पर विस्तृत बोली- पूर्व बैठक आयोजित की गई थी। कहा गया था कि आठ संभावित बोलीदाताओं ने भाग लिया था द्वारा कई पृष्ठों में चलने वाली बोली- पूर्व बैठकों के कार्यवृत्त ने प्रत्यर्थी निगम के पक्ष में कई शर्तों को बदल दिया ताकि अनुबंध निष्पादन की जिम्मेदारियों को द्वारा भी सख्त किया जा सके द्वारा इस प्रकार दो शुद्धिपत्र जारी करके निविदा का हिस्सा बन गया। बोली की तैयारी, बोलियों के मूल्यांकन और अनुबंध के पुरस्कार के लिए पर्याप्त समय देने के लिए अनुबंध की आवश्यकताओं यानी संभावित बोलीदाताओं की राय को समझने के लिए बोली-पूर्व बैठक आयोजित की गई थी। उक्त गतिविधियों को पूरा करने में एक महीने का समय लगा और इसे किसी भी तरह से जल्दबाजी की प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है। [पैरा 18] [112-डी-एच]

3.1 पृथक्करण का प्रश्न जैसा कि धारा 57 में निहित है। अनुबंध अधिनियम केवल पैरा्परिक वादों से युक्त एक समग्र समझौते के मामले में उत्पन्न होता है। किसी आदेश या समझौते की वैधता या अन्यथा तय करने के लिए उचित परीक्षण "पर्याप्त पृथकता" है न कि "पाठगत विभाज्यता"। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मुख्य

या महत्वपूर्ण भाग को बनाए रखते हुए तुच्छ और तकनीकी भागों को अलग और अलग करे और यदि यह कानूनी, वैध और अन्यथा प्रवर्तनीय है तो बाद वाले को प्रभावी बनाए। [पैरा 24] [116-डी-एफ]

3.2 अनन्य विज्ञापन अधिकारों से संबंधित अपीलकर्ता का प्रस्ताव अनावश्यक और अलग करने योग्य था, और उस कार्य का हिस्सा नहीं था जिसके लिए निविदा जारी की गई थी। नगर निगम, जो राज्य का एक सांविधिक निकाय और साधन है, को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभी पात्र लोगों के लिए इसे खुला रखते हुए निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए था। इस प्रकार, प्रत्यर्थी सं. 3- नगरपालिका निगम के लिए निविदा आमंत्रित किए बिना अपीलार्थियों को विज्ञापन अधिकार देना उचित नहीं था। उस हद तक, प्रतिवादी-आतंकवाद ने निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं किया है। इस प्रकार, जिस तरीके से कार्य आदेश के साथ अपीलार्थियों को विज्ञापन अधिकार दिए जाते हैं, उसे उचित नहीं कहा जा सकता है और उस हद तक अनुबंध को शेष कार्य आदेश में हस्तक्षेप किए बिना रद्द किया जा सकता है। [पैरा 21,23] [115-ईः116-ए-सी}

बी. ओ. आई. फाइनेंस लिमिटेड बनाम अभिरक्षक और अन्य (1997) 10 एससीसी 488: 1997 (3) एस. सी. आर. 51; शिन सैटेलाइट पब्लिक कं. लिड बनाम जैन स्टूडियो लिमिटेड (2006) 2 एस. सी. सी. 628: 2006 (1) एस. सी. आर. 933- पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

2014 (1) एस. सी. आर. 959	में निर्दिष्ट	पैरा 7
1994 (2) पूरक एस. सी. आर. 122	पर निर्भर था	पैरा 12
2000 (1) एस. सी. आर. 505	पर निर्भर था	पैरा 13

2006 (10) पूरक एस. सी. आर. 606 पर निर्भर था पैरा 14

1997 (3) एस. सी. आर. 51 पर निर्भर था पैरा 24

2006 (1) एस. सी. आर. 933 पर निर्भर था पैरा 24

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 9151-9152/2015

उच्च न्यायालय बॉम्बे की औरंगाबाद पीठ के रिट याचिका संख्या 7843/2014 में 14.10.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों की ओर से डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रणब कुमार मलिक, नीरज सिंह, सुश्री मीनाक्षी मिधा, श्रीमती सोमा मलिक, अमित दया, सेबत कुमार देवरिया, एल. निधिराम शर्मा, प्रणब कुमार मलिक।

प्रतिवादीओं के लिए श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुधांशु एस. चौधरी, वात्सल्य विज्ञान, आशीष प्रसाद, ए. विरमानी, रोहित शर्मा, हरीश पांडे, नाहुश शाह, सुश्री रमनी तनेजा, सुश्री सविता सिंह, कुणाल ए. चीमा, निशांत कटनेश्वरकर।

न्यायालय का निर्णय प्रफुल्ल सी. पंत, जे. द्वारा दिया गया था।

1. ये अपीलें बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 14.10.2014 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं, जिसके तहत 2014 की रिट याचिका संख्या 7843 और 2014 की 8211 की अनुमति दी जाती है, और 03.09.2014 का कार्य आदेश और अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 3 के बीच परिणामी समझौते को रद्द कर दिया जाता है।

2. मामले के तथ्यों को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 01.08.2014 को प्रतिवादी नं. 3- औरंगाबाद नगर निगम (संक्षेप में "नगर निगम") ने मौजूदा स्ट्रीट लाइटों को लाइट एमिटिंग डायोड (एल. ई. डी.) फिटिंग द्वारा बदलने के लिए निर्माण,

संचालन और हस्तांतरण (बी. ओ. टी.) आधार पर स्ट्रीट लाइट बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं। ठेकेदार को एक वर्ष के भीतर परियोजना को पूरा करना था और आठ वर्षों की अवधि में छियानबे समान मासिक किश्तों (ई. एम. आई.) द्वारा से नगर निगम से भुगतान की वसूली करनी थी। ई-निविदा सूचना का जवाब दो अलग-अलग भागों में दिया जाना आवश्यक था, अर्थात् तकनीकी बोली और मूल्य बोली निविदा सूचना के अनुसार, निविदा प्रपत्र 01.08.2014 से 20.08.2014 तक उपलब्ध कराए गए थे। बोलियां जमा करने की अवधि 28.08.2014 तक बढ़ा दी गई थी।

3. निविदा सूचना में अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें शामिल थीं:

> "(i) एल. ई. डी. लाइटों के निर्माता या पंजीकृत खंड ए विद्युत ठेकेदार और निविदा में भाग लेने के लिए पात्र हैं।
>
> (ii) क्लास ए विद्युत ठेकेदार (प्रमुख भागीदार) केवल एलईडी लाइट फिटिंग के निर्माता के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता करके भाग ले सकते हैं।
>
> (iii) एल. ई. डी. लाइट फिटिंग्स का निर्माता (प्रमुख भागीदार) ए श्रेणी के विद्युत ठेकेदार के साथ एक संयुक्त उद्यम बना सकता है।
>
> (iv) एल. ई. डी. लाइटों का निर्माता (प्रमुख भागीदार) विद्युत वस्तुओं के किसी अन्य निर्माता के साथ एक संयुक्त उद्यम बना सकता है, बशर्ते कि प्रमुख भागीदार ने निविदा बी. ओ. टी. परियोजना के निष्पादन के लिए क्लास ए विद्युत ठेकेदार के साथ एक समझौता ज्ञापन किया हो।

(v) बोली लगाने वाले को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में न्यूनतम रु 25 करोड़, तीन वर्षों में कुल 75 करोड़।

(vi) निविदा पत्रों के साथ जमा किए जाने वाले ई. एम. डी. के लिए बिक्री कर/वैट पंजीकरण, विनिर्माण प्रमाण पत्र और डी. डी. की सत्यापित वास्तविक प्रतियां।

(xiv) बोलीदाता वाणिज्यिक और तकनीकी शर्तों को संयुक्त रूप से पूरा करने के लिए अधिकतम दो कंपनियों/फर्मों का संयुक्त उद्यम हो सकता है।"

4. वर्तमान अपीलार्थियों और प्रत्यर्थी सं 1/रिट याचिकाकर्ताओं ने अपनी बोलियां प्रस्तुत कीं लेकिन बाद की तकनीकी बोलियों को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वे निविदा के अनुसार शर्तों को पूरा नहीं करते थे।

नोटिस करें- अपीलार्थियों की मूल्य बोली पर प्रतिवादी-नगर निगम द्वारा बातचीत की गई थी, और प्रस्ताव निगम की स्थायी समिति को भेजा गया था। इसके बाद, प्रस्ताव के अनुसार, अपीलार्थियों के पक्ष में कार्य आदेश जारी किया गया था।

5. अयोग्य ठहराए गए दोनों बोलीदाताओं ने अपनी अयोग्यता और अपीलकर्ताओं की बोली की स्वीकृति को चुनौती देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद पीठ के समक्ष रिट याचिकाएं (2014 का डब्ल्यू. पी. संख्या 7843 और 2014 का 8211) दायर कीं। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के माध्यम से कहा कि हालांकि रिट याचिकाकर्ताओं की अयोग्यता सही थी, लेकिन जिन अपीलार्थियों को कार्य आदेश दिया गया था, उन्हें असाधारण पक्ष दिखाया गया था, इसलिए इन अपीलों को रद्द कर दिया गया था।

6. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि रिट याचिकाकर्ताओं ने उच्च

न्यायालय के आदेश को चुनौती नहीं दी है, जिसके तहत नगर निगम द्वारा उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा गया है। रिट याचिकाकर्ताओं की तकनीकी बोली की अयोग्यता और अस्वीकृति मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन कारणों पर आधारित थीः-

(i) न तो रिट याचिकाकर्ता और न ही उसका संयुक्त उद्यम भागीदार एक पंजीकृत वर्ग-ए ठेकेदार था, और न ही उनमें से किसी को एलईडी रोशनी का निर्माता कहा गया था।

(ii) किसी भी रिट याचिकाकर्ता ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 25 करोड़ रुपये का न्यूनतम कारोबार हासिल नहीं किया था।

(iii) रिट याचिकाकर्ता परीक्षण के उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के नमूनों के न्यूनतम तीस टुकड़े जमा करने में विफल रहे।

7. जहां तक रिट याचिकाकर्ताओं की अयोग्यता की बात है (वर्तमान प्रतिवादी सं। 1) संबंधित है, इसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है। हमारे द्वारा विचार किए जाने वाला एकमात्र बिंदु यह है कि क्या उच्च न्यायालय, यह पता लगाने के बाद भी कि रिट याचिकाकर्ताओं की तकनीकी बोलियों को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था, अपीलार्थियों को दिए गए कार्य आदेश को रद्द करने में उचित था, जिनकी तकनीकी बोली नगर निगम द्वारा स्वीकार की गई थी।

8. अपीलार्थियों की ओर से उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पर आक्षेप करते हुए निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गईः

(1) आरई. समझौता ज्ञापन की अनुपस्थिति में

क) कि अपीलार्थियों ने विधिवत प्रविष्ट कियाः निविदा के खंड 1 (4) में आवश्यकतानुसार ए श्रेणी के विद्युत ठेकेदार मेसर्स मातोश्री इलेक्ट्रिकल्स एंड वाइंडिंग वर्क्स के साथ 14.08.2014 पर समझौता ज्ञापन।

ख) ए. एम. सी. द्वारा तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा गया है कि समझौता ज्ञापन याचिकाकर्ताओं द्वारा विधिवत दाखिल किया गया था।

ग) कि रिट याचिकाकर्ताओं ने अपनी रिट याचिकाओं और यहां तक कि संशोधित रिट याचिकाओं में भी इस बिंदु को कभी नहीं उठाया। यही कारण है कि उच्च न्यायालय के समक्ष समझौता ज्ञापन दायर नहीं किया गया था।

घ) कि यह एक ऑनलाइन निविदा होने के कारण, सभी पक्षों द्वारा दायर किए गए सभी दस्तावेज सभी के लिए सुलभ थे। चूंकि समझौता ज्ञापन अपलोड किया गया था, इसलिए इस मुद्दे को रिट याचिका में नहीं उठाया गया था।

(2) आरई. वैट वापसी की सत्यापित प्रतियों का गैर-प्रस्तुतिकरणः

क) कि अपीलकर्ताओं ने निविदा के खंड 1.2 (1) (ग) के संदर्भ में वैट विवरणी की सत्यापित प्रतियां विधिवत दाखिल की थीं। ए. एम. सी. द्वारा तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके द्वारा वैट रिटर्न विधिवत दाखिल किए गए थे।

ख) कि रिट याचिकाकर्ताओं ने अपनी रिट याचिकाओं और यहां तक कि संशोधित रिट याचिकाओं में भी इस बिंदु को कभी नहीं उठाया। यही कारण है कि उच्च न्यायालय के समक्ष वैट रिटर्न की प्रतियां दाखिल नहीं की गईं।

ग) कि यह एक ऑनलाइन निविदा होने के कारण, सभी पक्षों द्वारा दायर किए गए सभी दस्तावेज सभी के लिए सुलभ थे। चूंकि वैट रिटर्न अपलोड किए गए थे, इसलिए यह मुद्दा रिट याचिका में नहीं उठाया गया था।

घ) कि उच्च न्यायालय ने यह मानते हुए गलती की कि संयुक्त उद्यम भागीदार जिसका किसी विशेष वित्तीय वर्ष में शून्य कारोबार था, उसे भी वैट रिटर्न दाखिल करना पड़ा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल कारोबार की आवश्यकता को स्थापित करने के लिए वैट वापसी की आवश्यकता थी। इस प्रकार एक संयुक्त उद्यम भागीदार को केवल

तभी वैट रिटर्न दाखिल करना पड़ता था जब उसका कारोबार शून्य से अधिक हो।

(3) री. परिवर्त्तन आवश्यकताः

क) कि खंड 1 (5) में यह अपेक्षा की गई है कि बोली लगाने वाले ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में प्रत्येक को न्यूनतम 25 करोड़ रु., 3 वर्षों में कुल 75 करोड़। खंड 1.1 (14) निर्दिष्ट करता है कि बोलीदाता वाणिज्यिक और तकनीकी शर्तों को संयुक्त रूप से पूरा करने के लिए अधिकतम दो कंपनियों/फर्मों का संयुक्त उद्यम हो सकता है।

ख) कि दोनों संयुक्त उद्यम भागीदारों का संयुक्त कारोबार रु 25 करोड़ प्रति वर्ष और 75 करोड़ रु 3 साल में। यह तथ्य कि पी-1 का कारोबार शून्य था, महत्वहीन है क्योंकि आवश्यकता संयुक्त अनुपालन है।

ग) कि उच्च न्यायालय ने पैरा 28 में उल्लेख किया कि संयुक्त रूप से कारोबार की आवश्यकता को पूरा किया जाता है, लेकिन अपीलकर्ताओं के खिलाफ इस आधार पर गलती से अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलकर्ता संख्या 1 का कारोबार शून्य है।

(4), आरई. वित्तीय प्रस्ताव के रूप में दिनांकित उपचार पत्र 19.08.2014:

(क) कि 19.08.2014 दिनांकित पत्र की विषय वस्तु एक अलग उत्पाद और अलग अवधि की पेशकश थी, जो वर्तमान निविदा द्वारा कवर नहीं की गई थी। इसलिए इस पत्र के वित्तीय प्रस्ताव होने का सवाल ही नहीं उठा।

ख) कि 19.08.2014 दिनांकित पत्र में "निविदा की दिशा में अतिरिक्त सुझाव-बिना शर्त" विषय था और विशेष रूप से यह कहा गया था। ये सुझाव बिना शर्त हैं और औरंगाबाद शहर के सुधार के पक्ष में दिए जा रहे हैं। इन सुझावों को प्रतिग्रहण करना या अप्रतिग्रहण करना करना पूरी तरह से आपके विवेक पर होगा।

ग) ए. एम. सी. द्वारा पत्र पर अलग से विचार किया गया था। यह कार्य आदेश से स्पष्ट है। उच्च न्यायालय के समक्ष ए. एम. सी. के अतिरिक्त शपथ पत्र से भी इसकी

पुष्टि होती है।

घ) कि पत्र तकनीकी बोली के साथ अपलोड किया गया था। उच्च न्यायालय ने गलती से कहा कि तकनीकी बोली शुरू होने से पहले ही पत्र का खुलासा किया गया था, जो उसकी अपनी रिकॉर्डिंग के विपरीत है कि पत्र निविदा प्रस्ताव के साथ एक साथ प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में शाह इन्वेस्टमेंट्स की संशोधित रिट याचिका स्वयं दर्ज करती है कि 19.08.2014 दिनांकित पत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किया गया था।

ई) कि निविदा के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक आंकड़ा "सबसे कम बोली लगाने वाले = (VI)+(VII)+(VII) के मूल्यांकन के लिए एएमसी को कुल लागत" शीर्षक के तहत था। इस आंकड़े का खुलासा कहीं भी तकनीकी बोली में या 19.08.2014 दिनांकित पत्र में नहीं किया गया था। मूल्य बोली में 27 पृष्ठ शामिल थे और तकनीकी बोली के हिस्से के रूप में कोई भी पृष्ठ संलग्न नहीं किया गया था।

च) कि उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, दिनांकित 19.08.2014 पत्र से संबंधित कार्य आदेश का हिस्सा अलग करने योग्य है और भले ही उस हिस्से को अलग कर दिया गया हो, शेष अनुबंध बना रहता है।

(5) आरई. टेंडर की शर्तों के अलावा पोल पर विज्ञापन अधिकारों का उपचारः

कि कार्य आदेश दो भागों में है-एक मुख्य अनुबंध के पुरस्कार से संबंधित है और दूसरा अपीलार्थियों के अतिरिक्त सुझावों से संबंधित है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अतिरिक्त सुझावों से संबंधित भाग को मुख्य अनुबंध से अलग किया जा सकता है और कार्य आदेश से हटाने का निर्देश दिया जा सकता है। इस प्रकार, कार्य आदेश केवल मुख्य अनुबंध के पुरस्कार तक ही सीमित हो सकता है।

(6) आरई. ए. एम. सी. द्वारा जल्दबाजी में लिया गया निर्णयः

क) कि निविदा आमंत्रित करने की सूचना 01.08.2014 पर जारी की गई थी और पूरी प्रक्रिया 03.09.2014 पर पूरी की गई थी। इस प्रकार कोई अनुचित जल्दबाजी नहीं थी।

ख) कि बोलियां जमा करने के लिए समय अवधि दो बार बढ़ाई गई थी जो कथित जल्दबाजी के तथ्य को नकारती है।

ग) कि ए. एम. सी. के आयुक्त के स्थानांतरण के आदेश के कारण इस मामले पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि अंतिम निर्णय ए. एम. सी. की स्थायी समिति द्वारा लिया गया था।

(घ) निर्णय लेने की प्रक्रिया विवेक के उचित प्रयोग को दर्शाती है।

(7) अन्य सुझावः

क) कि उच्च न्यायालय ने संजय कुमार शुक्ला बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड [(2014) 3 एस. सी. सी. 493] मामले में इस न्यायालय के फैसले की सही ढंग से सराहना नहीं की, जहां इस न्यायालय ने संविदात्मक मामलों में रिट याचिकाओं पर विचार करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता को दोहराया, जब तक कि जनहित द्वारा उचित नहीं ठहराया जाता है, क्योंकि गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

ख) कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि उसके समक्ष याचिकाएं जनहित याचिकाएं नहीं थीं, बल्कि असफल बोलीदाताओं की याचिकाएं थीं।

ग) यह कि रिट याचिकाकर्ताओं के उद्देश्यों पर विचार नहीं किया गया, जिन्होंने यह जानने के बावजूद बोली लगाई कि वे आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। वास्तव में, शाह इन्वेस्टमेंट्स एक वित्त कंपनी थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता दूसरों के लिए अग्रणी व्यक्ति थे।

घ) उस रिट याचिकाकर्ता शाह इन्वेस्टमेंट के डब्ल्यू. पी. नंबर 7843/2014 में

संशोधन के बावजूद याचिकाकर्ताओं की बोली को रद्द करने का कोई अनुरोध भी नहीं था। वर्तमान अपीलों में अपीलकर्ता संख्या 2 को पॉलीकैब के डब्ल्यू. पी. संख्या 8211/2014 में भी पक्षकार नहीं बनाया गया था।

ई) यह विवादित आदेश दुर्भावनापूर्ण है, हालांकि रिट याचिकाओं में किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण आरोप नहीं थे।

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से, यह तर्क दिया जाता है कि विचाराधीन कार्य आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित कारणों से सही ढंग से रद्द कर दिया गया थाः-

(i) कि वर्तमान निविदा के लिए बोली दो-चरणीय ई-निविदा प्रक्रिया द्वारा आयोजित की जानी थी। बोली दस्तावेज के खंड 3 के अनुसार, पहले चरण में बोलीदाताओं को अपनी तकनीकी बोलियां जमा करने की आवश्यकता थी, और इनमें से स्वीकार्य बोलियों को क्षेत्रीय परीक्षणों के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जानी थीं जिनके नमूने तकनीकी चरण में योग्य थे।

(ii) वह खंड 1.2 (एच) निर्धारित करता है कि यदि कोई बोलीदाता तकनीकी बोली के साथ मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो निविदा बोली को वापस लिया गया माना जाएगा और ई. एम. डी. जब्त कर लिया जाएगा।

(iii) कि यह निविदा की एक आवश्यक और अनिवार्य शर्त थी जिसका अर्थ "होगा" शब्द के उपयोग और इस खंड के भंग से जुड़े परिणाम, यानी बोली को वापस लिया गया माना जाता है और इसके परिणामस्वरूप ई. एम. डी. जमा की जब्ती से लगाया जा सकता है।

(iv) यह तय किया गया कानून है कि जहां आवश्यक शर्तें हैं, उनका पालन

किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी संख्या 3- निगम के पास बोली दस्तावेज की किसी भी शर्त में ढील देने की कोई शक्ति नहीं है, और किसी भी स्थिति में इस संदर्भ में ऐसी किसी भी शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि बोली दस्तावेज की अनिवार्य शर्त का पालन करने से कोई छूट नहीं दी जा सकती है।

(v) अपीलार्थियों का यह तर्क कि 19 अगस्त, 2014 के पत्र में निहित प्रस्ताव एक बिना शर्त प्रस्ताव था जो केवल प्रत्यर्थी सं. 3- निगम अपीलार्थियों को बोली दस्तावेज की शर्तों के भंग के परिणामों से नहीं बचा सकता है।

(vi) कि 19 अगस्त, 2014 के उक्त पत्र में निम्नलिखित प्रस्ताव और सुझाव शामिल हैं जिनका अपीलार्थियों द्वारा दिए गए मूल्य प्रस्ताव पर सीधा असर पड़ता हैः

ए) पत्र में बताया गया कि अपीलकर्ता निविदा के तहत न्यूनतम गारंटी अवधि के लिए प्रति माह रुपये 95- प्रति स्थिरता की दर से अपनी सेवाओं की पेशकश करेंगे।

बी) पत्र में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन निगरानी प्रणाली को लागू करने से बोली दस्तावेज की आवश्यकता के अनुसार उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण पैनलों की संख्या 1200 से घटकर 600 हो जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि अपीलकर्ताओं द्वारा कीमत में कोई संबंधित कमी की पेशकश नहीं की गई थी। हालांकि, यदि आवश्यक नियंत्रण पैनलों की संख्या 600 से अधिक बढ़ानी थी, तो अपीलकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 3- निगम की अतिरिक्त लागत पर इसे स्थापित करेंगे। यह एक प्रकार का प्रस्ताव है जो स्पष्ट रूप से एक सौदे पर बातचीत करने में अपीलार्थियों के शरारती इरादे को उजागर करता है जो विशुद्ध रूप से सरकारी खजाने की कीमत पर अपने लिए फायदेमंद होगा।

ग. पत्र में पूरी बी. ओ. टी. अवधि के लिए स्ट्रीट लाइटों पर विशेष विज्ञापन अधिकार दिए जाने पर विचार करते हुए इन नई तकनीकों को लागू करने का प्रस्ताव

भी दिया गया।

(vii) कि उक्त पत्र में दिए गए प्रस्ताव और सुझाव, चाहे वे सशर्त हों या बिना शर्त, निर्विवाद रूप से एक मूल्य प्रस्ताव थे, जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 3-निगम द्वारा जारी 3 सितंबर, 2014 के कार्य आदेश से स्पष्ट है।

(viii) कि इस तरह के पत्र को प्रस्तुत करने से वास्तव में अपीलकर्ताओं की बोली अनुत्तरदायी हो जाती है, जिसे "वापस लिया गया और ई. एम. डी. जब्त" माना जाता है। बोली दस्तावेज़ की शर्तें प्रत्यर्थी संख्या 3- निगम को किसी भी व्यक्तिगत बोलीदाता के लिए एकतरफा रूप से अपनी शर्तों में ढील देने का अधिकार नहीं देती हैं, इस तरह से जो ऐसे बोलीदाता को बोली दस्तावेज़ की अनिवार्य और आवश्यक शर्तों को दरकिनार करने की अनुमति देगा।

(ix) कि तकनीकी बोली के साथ इस तरह का मूल्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद, अपीलकर्ता तकनीकी स्तर पर अयोग्य हो गए और इसलिए, इस बारे में कोई सवाल नहीं उठता है कि क्या प्रतिवादी संख्या 3-निगम अपीलकर्ताओं के इन अतिरिक्त प्रस्तावों और सुझावों को प्रतिग्रहण करना या अप्रतिग्रहण करना करने का विकल्प चुन सकता है।

(x) कि निविदा के बाद की बातचीत में शामिल होने की प्रथा की निंदा की गई है और इसे भ्रष्टाचार के स्रोत के रूप में लेबल किया गया है और उसी के अनुसरण में, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 3 मार्च, 2007 को परिपत्र सं॰ 04/03/07 जारी किया है और अनिवार्य किया है कि कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर एल-1 के साथ कोई निविदा के बाद की बातचीत नहीं की जानी चाहिए, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। मान लीजिए, वर्तमान मामले में ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं है।

(xi) कि 3 सितंबर, 2014 के कार्य आदेश में निहित इन अतिरिक्त प्रस्तावों और

सुझावों की स्वीकृति के परिणामस्वरूप निविदा का दायरा बढ़ा है। निविदा की अवधि को दो साल की विस्तारित गारंटी अवधि के साथ आठ साल से बढ़ाकर चार साल की विस्तारित गारंटी अवधि के साथ आठ साल कर दिया गया है। उत्तरदाता प्रत्यर्थी/रिट याचिकाकर्ता अतिरिक्त दो साल की गारंटी प्रदान करने के बदले में मुआवजे की मांग करता है। पूरे अनुबंध अवधि के लिए विशेष विज्ञापन अधिकारों के अनुदान को शामिल करने के लिए निविदा कार्य का दायरा भी बढ़ाया गया है, जिसे अब बिना किसी विचार के बारह वर्षों के लिए संशोधित किया गया है। ये निविदा की आवश्यक शर्तों से प्रमुख विचलन हैं जिनकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(xii) दलीलों के दौरान अपीलकर्ताओं ने बार में कुछ अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि अतिरिक्त प्रस्तावों की स्वीकृति की गई है। उचित विचार के बाद तथापि, 2 सितंबर, 2104 के अपीलार्थियों के पत्र, 2 सितंबर, 2014 की आयुक्त की अध्यक्षता में औरंगाबाद नगर आयोग की बैठक के कार्यवृत्त और 3 सितंबर, 2014 की औरंगाबाद नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक के कार्यवृत्त जैसे उक्त दस्तावेजों का केवल अवलोकन ही निविदा की पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के जल्दबाजी के तरीके का संकेत देगा।

10. नगर निगम के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों पर आक्षेप करते हुए अपीलार्थियों द्वारा लिए गए आधारों का सारतः समर्थन किया है।

11. हमने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है, और अभिलेख पर कागजात का अध्ययन किया है।

12. 'टाटा सेल्युलर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' में, इस अदालत ने प्रशासनिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा के दायरे और अनुबंध देने की शक्तियों के प्रयोग से

संबंधित निम्नलिखित सीमाओं को माना है। पैरा 94 में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

"94. उपरोक्त से जो सिद्धांत निकाले जा सकते हैं वे हैं:

(1) आधुनिक प्रवृत्ति प्रशासनिक कार्रवाई में न्यायिक संयम की ओर इशारा करती है।

(2) न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है, बल्कि केवल निर्णय लेने के तरीके की समीक्षा करता है।

(3) न्यायालय के पास प्रशासनिक निर्णय को सही करने की विशेषज्ञता नहीं है। यदि प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा की अनुमति दी जाती है, तो यह आवश्यक विशेषज्ञता के बिना अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करेगा, जो स्वयं गलत हो सकता है।

(4) निविदा के निमंत्रण की शर्तें न्यायिक जांच के लिए खुली नहीं हो सकती हैं क्योंकि निविदा का निमंत्रण अनुबंध के दायरे में है। आम तौर पर, निविदा प्रतिग्रहण करना करने या अनुबंध देने का निर्णय कई स्तरों द्वारा से बातचीत की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अक्सर, इस तरह के निर्णय विशेषज्ञों द्वारा गुणात्मक रूप से किए जाते हैं।

(5) सरकार को अनुबंध की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जोड़ों में एक निष्पक्ष खेल एक प्रशासनिक क्षेत्र या अर्ध-प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रशासनिक निकाय के लिए एक आवश्यक संगत है। हालाँकि, निर्णय का परीक्षण न केवल वेड्सबरी के विकर्णता के सिद्धांत (ऊपर बताए गए इसके अन्य तथ्यों सहित) के अनुप्रयोग द्वारा किया जाना चाहिए, बल्कि यह स्वतंत्र मनमाना होना चाहिए जो

पूर्वाग्रह से प्रभावित न हो या दुर्भावना से प्रेरित न हो।

(6) निर्णयों को रद्द करने से प्रशासन पर भारी प्रशासनिक बोझ पड़ सकता है और इससे बढ़े हुए और बिना बजट के खर्च हो सकते हैं।

13. एयर इंडिया लिमिटेड में बनाम कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड और अन्य, इस न्यायालय ने यह सिद्धांत निर्धारित किया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए अनुबंध देने के मामलों में अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन शक्ति का सावधानीपूर्वक उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। पैरा 7 में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः-

"7.....अंततः ए द्वारा उसे दिए गए प्रस्तावों में से एक को प्रतिग्रहण करना करने का निर्णय लेने से पहले यह बातचीत में प्रवेश कर सकता है। अनुबंध देने के लिए कीमत हमेशा एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए। यदि निविदा की शर्तें इस तरह की छूट की अनुमति देती हैं, तो प्रामाणिक कारणों से कोई भी छूट देने के लिए स्वतंत्र है। यह प्रस्ताव को प्रतिग्रहण करना नहीं कर सकता है, भले ही यह सबसे अधिक या सबसे कम हो। लेकिन राज्य, उसके निगम, उपकरण और एजेंसियां उनके द्वारा निर्धारित मानदंडों, मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं और मनमाने ढंग से उनसे अलग नहीं हो सकते हैं। हालाँकि वह निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन न्यायालय निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच कर सकता है और यदि यह दुर्भावना, अनुचितता और मनमानेपन से दूषित पाया जाता है तो हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य, उसके निगमों, उपकरणों और एजेंसियों का सार्वजनिक कर्तव्य है कि वे सभी संबंधित लोगों के

प्रति निष्पक्ष रहें। यहां तक कि जब निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुछ दोष पाया जाता है, तब भी न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए और इसका उपयोग केवल लोक हित को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए, न कि केवल कानूनी मुद्दे को बनाने के लिए। न्यायालय को हमेशा व्यापक जनहित को ध्यान में रखना चाहिए आदेश यह तय किया जा सके कि उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं। केवल तभी जब यह निष्कर्ष निकलता है कि भारी जनहित में हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए।"

14. जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया हैः

22. प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य मनमानेपन, तर्कहीनता, अनुचितता, पूर्वाग्रह और दुर्भावना को रोकना है। इसका उद्देश्य यह जांचना है कि क्या विकल्प या निर्णय "कानूनी रूप से" किया गया है और यह जांचना नहीं है कि विकल्प या निर्णय "सही" है या नहीं। जब निविदाओं या अनुबंधों के पुरस्कार से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया जाता है, तो कुछ विशेष विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक अनुबंध एक वाणिज्यिक लेनदेन है। निविदाओं का मूल्यांकन करना और अनुबंध देना अनिवार्य रूप से वाणिज्यिक कार्य हैं। समानता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एक दूरी पर रहते हैं। यदि अनुबंध देने से संबंधित निर्णय प्रामाणिक है और जनहित में है, तो अदालतें न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप नहीं करेंगी, भले ही

किसी निविदाकर्ता के लिए प्रक्रियात्मक विचलन या मूल्यांकन में त्रुटि या पूर्वाग्रह बनाया गया हो। न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सार्वजनिक हित की कीमत पर निजी हित की रक्षा करने या संविदात्मक विवादों को तय करने के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिकायत वाला निविदाकार या ठेकेदार हमेशा दीवानी अदालत में हर्जाने की मांग कर सकता है। काल्पनिक शिकायतों, घायल गर्व और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के साथ असफल निविदाकारों द्वारा किए गए प्रयासों का विरोध किया जाना चाहिए, कुछ तकनीकी/प्रक्रियात्मक उल्लंघन या स्वयं के प्रति कुछ पूर्वाग्रह के मोलहिल से पहाड़ बनाने के लिए, और न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके अदालतों को हस्तक्षेप करने के लिए राजी करना चाहिए। इस तरह के हस्तक्षेप, या तो अंतरिम या अंतिम, सार्वजनिक कार्यों को वर्षों तक रोक सकते हैं, या हजारों और लाखों लोगों को राहत और सहायता में देरी कर सकते हैं और परियोजना की लागत को कई गुना बढ़ा सकते हैं।

15. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमने वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच की। मान लीजिए, प्रतिवादी संख्या 3 नगर निगम ने मौजूदा स्ट्रीट लाइटों को एलईडी फिटिंग द्वारा बदलने के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित कीं। ई-टेंडर तकनीकी बोली और मूल्य बोली से किया जाना आवश्यक था। यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी नं. 1 ने अपनी तकनीकी बोली अपलोड की और नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल पर अलग से मूल्य/वित्तीय बोली प्रस्तुत की। पार्टियों के बीच यह भी स्वीकार किया जाता है कि निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि शुरू में 20.08.2014 थी, जिसे 28.08.2014 तक बढ़ा दिया गया था। तीनों बोलीदाताओं का तकनीकी मूल्यांकन उनकी उपस्थिति में

किया गया। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि रिट याचिका दायर करने वाले अन्य दो बोलीदाताओं की अयोग्यता को उच्च न्यायालय ने सही पाया और कहा कि इस तथ्य को हमारे सामने चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रकार, केवल इस मुद्दे की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या अपीलार्थियों की तकनीकी बोली को उन्हें अनुचित पक्ष दिए बिना कानून के तय किए गए सिद्धांत के अनुसार अनुमोदित किया गया था या नहीं।

16. उच्च न्यायालय ने विवादित आदेशों में कहा है कि अपीलकर्ताओं और एलईडी निर्माता मेसर्स मातोश्री इलेक्ट्रिकल्स एंड वाइंडिंग वर्क्स के बीच समझौता ज्ञापन को रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय इस पर ध्यान देने में विफल रहा। किसी भी रिट याचिकाकर्ता ने उस आधार पर अपीलकर्ताओं की बोली की स्वीकृति को चुनौती नहीं दी थी, और अपीलकर्ताओं को इसे अदालत के रिकॉर्ड पर रखने का कोई अवसर नहीं था-समझौता ज्ञापन निविदा बोली का हिस्सा था, और इसका उल्लेख "निविदा समिति के मूल्यांकनः 'रिपोर्ट करें'। उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश में उल्लिखित अपीलार्थियों के खिलाफ प्रतिकूल दृष्टिकोण रखने का एक अन्य कारण यह है कि अपीलार्थियों द्वारा वैट विवरणी की सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई थीं। हमारे सामने यह बताया गया है कि प्रासंगिक वित्तीय वर्षों के लिए वैट रिटर्न का विवरण तकनीकी बोली के साथ अपीलकर्ताओं द्वारा विधिवत दाखिल किया गया था। रिकॉर्ड से पता चलता है कि तकनीकी बोलियों के साथ वैट रिटर्न दाखिल करने की पुष्टि "निविदा समिति मूल्यांकन रिपोर्ट" से भी होती है। ""बोलीदाता के वैट रिटर्न" की आवश्यकता के बारे में उक्त रिपोर्ट में समिति ने उल्लेख किया है-"ठीक है। "10 ए, 10 बी, 10 सी, 10 डी", और प्रमुख को परिचित करें- "निविदा शर्त अनुपालन" शब्द "हां" का उल्लेख किया गया है। पँचिश करोड़ रुपये के कारोबार की शर्त के संबंध में, उच्च न्यायालय ने स्वयं कोई कमजोरी नहीं पाई और कहा कि अपीलकर्ताओं ने पिछले प्रत्येक वित्तीय वर्ष

में पँचिश करोड़ रुपये की वापसी की शर्त को पूरा किया क्योंकि संयुक्त उद्यम भागीदार के कारोबार को ध्यान में रखा जाना था।

17. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि पैदल चलने वालों और मोटर चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय बिजली संहिता को शामिल करते हुए निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा में लक्स स्तरों को प्राप्त करने और आठ वर्षों तक बनाए रखने के लिए भी निर्दिष्ट किया गया था। बिजली की खपत की गारंटी की आवश्यकता थी और ठेकेदार को उद्धृत ऊर्जा बिल पर वास्तविक ऊर्जा बिल की अधिकता के बीच के अंतर को वहन करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। ठेकेदार को बी. ओ. टी. अवधि के दौरान सभी स्थापित उपकरणों के व्यापक रखरखाव के लिए जिम्मेदार बनाया गया था, जिसमें कोई भी टूटना, चोरी, किसी भी खाते में नुकसान शामिल था। यहां यह उल्लेख करना सार्थक है कि बोली-पूर्व बैठक में आठ बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और निविदा सूचना के संबंध में विभिन्न बिंदुओं को स्पष्ट किया।

18. हमारी राय में, नगर निगम की ओर से अनुबंध देने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई देती है क्योंकि निविदा 01.08.2014 पर जारी की गई थी और इसे केवल 03.09.2014 पर अंतिम रूप दिया गया था, यानी एक महीने से अधिक की अवधि के बाद। बोली-पूर्व बैठकें आयोजित की गईं और निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दो बार 20.08.2014 से 25.08.2014 और उसके बाद 28.08.2014 तक बढ़ा दी गई, जिससे पता चलता है कि प्रक्रिया जल्दबाजी में नहीं की गई थी। 12.08.2014 पर विस्तृत बोली-पूर्व बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कहा गया था कि आठ संभावित बोलीदाताओं ने भाग लिया था द्वारा कई पृष्ठों में चलने वाली बोली-पूर्व बैठकों के कार्यवृत्त ने प्रत्यर्थी निगम के पक्ष में कई शर्तों को बदल दिया ताकि अनुबंध निष्पादन की जिम्मेदारियों को द्वारा भी सख्त बनाया जा सके द्वारा इस प्रकार दो शुद्धिपत्र जारी करके निविदा का हिस्सा बन गया। बोली-पूर्व बैठक अनुबंध की आवश्यकताओं को

समझने के लिए आयोजित की गई थी, जैसे कि संभावित बोलीदाताओं की राय, बोली की तैयारी, बोलियों के मूल्यांकन और अनुबंध के पुरस्कार के लिए पर्याप्त समय देना। उक्त गतिविधियों को पूरा करने में एक महीने का समय लगा और इसे किसी भी तरह से जल्दबाजी की प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है।

19. इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने कानून में यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि कार्य आदेश एल. ई. डी. फिटिंग द्वारा स्ट्रीट लाइटों के प्रतिस्थापन और बी. ओ. टी. आधार पर स्ट्रीट लाइट बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के संबंध में अपीलार्थियों को अवैध रूप से दिया गया था।

20. अब, हम कार्य आदेश और परिणामी समझौते के उस हिस्से पर आते हैं जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा नगर निगम को भेजे गए दिनांकित 19.08.2014 पत्र के आधार पर अपीलकर्ताओं को विज्ञापन अधिकार भी दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने दिनांकित (तकनीकी बोली जमा करने से एक दिन पहले) पत्र पर गंभीरता से ध्यान दें है जिसमें अपीलकर्ताओं ने नगर निगम को "कुछ सुझाव" दिए हैं। उक्त पत्र की प्रतिलिपि नीचे दी गई हैः-

"आयुक्त, औरंगाबाद नगर निगम, औरंगाबाद, महाराष्ट्र

उपःनिविदा के लिए अतिरिक्त सुझाव -

बिना शर्त

आदरणीय साहब,

हम 21 अगस्त, 2014 को खोले जाने वाले एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग के लिए निविदा में भाग ले रहे हैं और आपके विचार के लिए इसके लिए कुछ अतिरिक्त सुझाव हैं। ये सुझाव बिना शर्त हैं और औरंगाबाद शहर के सुधार के पक्ष में दिए जा रहे हैं। इन सुझावों को प्रतिग्रहण करना या अप्रतिग्रहण करना करना पूरी तरह से आपके

विवेक पर होगा।

हम स्विचिंग पॉइंट से स्ट्रीट लाइट्स के ऑनलाइन इंटरनेट आधारित नियंत्रण और निगरानी को लागू करने की पेशकश कर सकते हैं। उपयुक्त प्रणालियाँ जी. एस. एम. आधारित मोडेम का उपयोग स्ट्रीट लाइटों के चालू और बंद होने को नियंत्रित करने के लिए करेंगी, जिन्हें प्रत्येक नियंत्रण कक्ष में स्थापित किया जाएगा। हालांकि इस तरह की प्रणाली की लागत काफी अधिक है, लेकिन अब हम 36,000/- रुपये की कम कीमत पर समाधान को लागू करने की पेशकश कर रहे हैं। प्रति नियंत्रण पैनल के साथ-साथ इसकी ऑनलाइन निगरानी के लिए जी. एस. एम. संचार और सॉफ्टवेयर की आवर्ती लागत, बशर्ते कि सभी स्ट्रीट लाइट्स पोल के लिए विशेष विज्ञापन अधिकार हमें दिए गए हों।

निविदा के अनुसार नियंत्रण पैनलों की निर्धारित संख्या लगभग 1200 है। यदि नई प्रौद्योगिकी ऑनलाइन नियंत्रण प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया जाता है, तो हम पैरा्परिक रूप से मौजूदा नियंत्रण पैनलों की संख्या को लगभग 600 तक कम करने की योजना बना सकते हैं, क्योंकि एलईडी रोशनी के कार्यान्वयन के बाद स्विचिंग पॉइंट प्रणाली का भार काफी कम हो जाएगा। इस प्रकार हम एएमसी के बोझ के बिना ऑनलाइन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कम नियंत्रण पैनलों की लागत की भरपाई कर सकते हैं। यदि लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण स्ट्रीट लाइटिंग को प्रस्तावित 600 पैनलों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो जो भी अतिरिक्त एन. ओ. एस. की आवश्यकता हो सकती है, उसकी लागत ए. एम. सी. द्वारा वहन की जाएगी।

ऑनलाइन निगरानी और नियंत्रण के कार्यान्वयन की दिशा में एक पैरा्परिक के रूप में, हम सभी स्ट्रीट लाइट पोल के लिए विशेष विज्ञापन अधिकार चाहते हैं।

2. दो साल की अतिरिक्त विस्तारित गारंटी अवधिः-

हम अतिरिक्त गारंटी अवधि को दो साल से बढ़ाकर चार साल कर सकते हैं, यदि ए. एम. सी. द्वारा आवश्यक हो, तो भाग डी के अनुसार लागत की समान शर्तों पर, यानी प्रति माह रुपये 95/- के भुगतान पर। यह प्रस्ताव है।

संयुक्त उद्यम बोलीदाता 3

(इलेक्ट्रॉन लाइटिंग सिस्टम (पी) लिमिटेड

और पैरागॉन केबल इंडिया)

एसडी/-

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता "

21. उपरोक्त पत्र से पता चलता है कि सुझाव बिना शर्त थे, जिससे नगर निगम के लिए इसे प्रतिग्रहण करना करने या न करने के लिए खुला छोड़ दिया गया। उपरोक्त उद्धृत पत्र द्वारा से अपीलकर्ताओं ने सुझाव दिया कि यदि स्ट्रीट लाइट के खंभे पर बोली लगाने वाले को विशेष विज्ञापन अधिकार दिए जाते हैं, तो बोली लगाने वाला कीमत में 36,000/- प्रति नियंत्रण कक्ष रुपये की कमी करेगा। नियंत्रण पैनल की निर्धारित संख्या 1,200/- थी, जिसे पैरा्परिक योजना द्वारा से घटाकर 600/- किया जा सकता था। हमारा विचार है कि विज्ञापन अधिकारों से संबंधित उपरोक्त प्रस्ताव अनावश्यक और अलग करने योग्य था, और उस काम का हिस्सा नहीं था जिसके लिए निविदा जारी की गई थी। अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी बी. ओ. टी. आधार पर स्ट्रीट लाइटों को एल. ई. डी. द्वारा बदलने से संबंधित कार्य अनुबंध के अनुसार उक्त पत्र का लाभ उठाए बिना काम को निष्पादित करने के लिए तैयार हैं।

22. प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि औरंगाबाद शहर में अन्य स्रोतों से विज्ञापन से राजस्व, वित्तीय वर्षों के लिए 2011-2012, 2012-2013 और 2013-2014 क्रमशः रु 81,31,091=00 81,15,438-00 और

89,03,976= 00 लेकिन स्ट्रीट लाइट पोल्स पर विज्ञापन से वही तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए शून्य था। इस प्रकार, नगर निगम ने कार्य आदेश देते समय अपीलार्थियों के साथ मामले पर बातचीत करने में कोई अवैधता नहीं की।

23. हमारी राय में, विज्ञापन अधिकारों के संबंध में मामला अलग था, और नगर निगम जो राज्य का एक वैधानिक निकाय और साधन है, को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभी पात्र लोगों के लिए इसे खुला करके निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए था। इस प्रकार, हम सोचते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 3 के लिए निविदा आमंत्रित किए बिना अपीलार्थियों को विज्ञापन अधिकार देना उचित नहीं था। उस हद तक, हमारी राय में, प्रतिवादी संख्या 3 ने निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं किया है। इस प्रकार, जिस तरीके से कार्य आदेश के साथ अपीलार्थियों को विज्ञापन अधिकार दिए जाते हैं, उसे उचित नहीं कहा जा सकता है और उस हद तक अनुबंध को शेष कार्य आदेश में हस्तक्षेप किए बिना रद्द किया जा सकता है।

24. बी. ओ. आई. में भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की खंड 57 में निहित पृथकता के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए, फाइनेंस लिमिटेड, बनाम कस्टोडियन और अन्य", इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि अलगाव का सवाल केवल पैरा्परिक वादों से युक्त एक समग्र समझौते के मामले में उत्पन्न होता है। शिन सैटेलाइट पब्लिक कंपनी लिमिटेड बनाम जैन स्टूडियो लिमिटेड, इस न्यायालय ने कहा है कि किसी आदेश या समझौते की वैधता या अन्यथा तय करने के लिए उचित परीक्षण "मूल विभाजन" है न कि "पाठ्य विभाजन"। इस न्यायालय द्वारा आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह मुख्य या महत्वपूर्ण भाग को बनाए रखते हुए तुच्छ और तकनीकी भागों को अलग और अलग करे और यदि यह कानूनी, वैध और अन्यथा प्रवर्तनीय है तो बाद वाले को प्रभावी बनाए।

25. इसलिए, तथ्यों और परिस्थितियों में और ऊपर चर्चा किए गए कारणों के लिए, अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी जानी चाहिए। तदनुसार, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेशों को इस हद तक दरकिनार कर देते हैं कि उसने अपीलकर्ताओं को मौजूदा स्ट्रीट लाइटों को एलईडी फिटिंग द्वारा बदलने और बीओटी आधार पर स्ट्रीट लाइट बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के संबंध में दिए गए कार्य अनुबंध को रद्द कर दिया है। अपीलार्थियों को उस हद तक दिया गया दिनांकित कार्य आदेश वैध रहेगा। हालांकि, कार्य अनुबंध में अपीलार्थियों को दिए गए विज्ञापन अधिकार रद्द ही रहेंगे। विज्ञापन अधिकारों के संबंध में, प्रत्यर्थी संख्या 3 अनुबंध देने से पहले निविदाएं आमंत्रित कर सकता है। अपीलों का निपटारा किया जाता है।

26. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।